राष्ट्रीय हिंदी, साप्ताहिक खबरें

जनती की समस्या, हर पल टाइम्स की खबर

HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

कार्यकारी संपादक : जमील जी. खान

RNI NO. MAHHIN/2011/24374

▸ वर्ष : १० ▸ अंक: १९ ▸ मुंबई, शुक्रवार, ८ जनवरी से १४ जनवरी २०२१ ▸ पृष्ठ: ४ ▸ मुल्य : २/- रु.

मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखंड, चेन्नई, कलकत्ता जानेवाला अखबार, (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करे)

ट्रैक्टर रैली के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन

ये तो बस झांकी है, कानून वापस नहीं हुए तो 26 को निकालेंगे परेड : किसान

नई दिल्ली,
पिछले लगभग डेढ़ महीने से किसान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अडिग हैं। वहीं सरकार भी कदम पीछे नहीं करना चाहती। ऐसे में विरोध में किसानों का हल्लाबोल जारी है। सरकार के साथ किसानों की सात दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसलिए किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है और आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसान आज यानी गुरुवार सुबह 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर गणतंत्र दिवस के लिए अपने 'ट्रैक्टर मार्च' का 'ड्रेस रिहर्सल' करेंगे।

इसके कारण NH-9 सहित दो नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों पर इस रिहर्सल का असर होने की संभावना है। हालांकि, योगेंद्र यादव ने कहा कि ये किसान आज दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे। इधर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने कहा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है।

भीषण ठंड, बारिश के बावजूद पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों के हजारों किसान पिछले 40 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने तथा दो अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी क्योंकि किसान तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के आने के बाद से दिल्ली यातायात पुलिस अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शहर में सड़कों के बंद होने के बारे में लोगों को लगातार सूचनाएं दे रही है।

- यूपी गेट पर भाकियू (अम्बावता) गुट ने 10 जनवरी को महापंचायत की घोषणा की। (शेष पेज 2 पर)

यह कहानि नहीं हकिकत है

Har pal tv news. cmw.cin.chief news Editor.Jameel g khan.Mumbai India.

हर पल टाइम्स की रिर्पोट ,

- किसानों को 40 दिन होने जा रहे है और 60 से ज्यादा जाने चली गई मगर सरकार पर कोई असर नहीं।
- देश के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे है, पुरे हिंदुस्तान में एक ही बात किसानों का मामला कब होगा खत्म, अफसोस नेशनल चॅनल छोटी खबरों को बढावा दे रहे है और जो किसानों की हकिकत और उनकी मुश्किलों को सामने नहीं लाया जा रहा है।
- किसानों की समस्या पुरे दुनिया में पहुंच रही है और हमारे सरकार पर असर नहीं हो रहा है।

1) हमारा बडा सवाल , क्या पुरे हिंदुस्तान की जनता किसानों को पुरी तरह साथ देंगी।

2) सरकार वैक्सीन कि किंमत लेंगी या मुफ्त में दि जायेगी? और वैक्सीन से नुकसान होता है तो क्या सरकार जवाबदार होगी?

3) हम चाहते है कि सबसे पहले किसानों के तीन कानूनवाला मामला तय करे सरकार वरना देश के हालात खराब हो जाएंगे।

4) देश में रोजगार की जरुरत है और समाज की जरुरतों को पुरा करे सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा राशन भी देना होगा।

5) मुंबई में लोकल ट्रेन जल्द से जल्द शुरु कर दी जाए और हर राज्यों में जाने वाली ट्रेनों को भी शुरु होनी चाहिए और खास बात तिकिट के दाम ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं इस पर ध्यान दे सरकार।

हिंदुस्तान की जनता ज्यादा समझदार है सरकार को ज्यादा समझाने की कोई जरुरत नहीं।

केंद्र सरकार पर बरसीं हरसिमरत कौर

पीएम मोदी को किसानों से करनी चाहिए बात : हरसिमरत कौर

नई दिल्ली,सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत के एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र समूचे किसान समुदाय का भरोसा खो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी किसानों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए। किसानों की पीड़ा पर अपना दुख प्रकट करते हुए बादल ने कहा, यह अजीब है कि किसान कंपकंपा देने वाली ठंड में खुले में रातें गुजार रहे हैं और बहरे कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंच पा रही है। लोकसभा में तीनों कृषि कानून पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वालीं बादल ने पीटीआई-भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले छह-सात हफ्ते में किसानों ने जो सामना किया है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ... अब जो स्थिति पैदा हुई है और विरोध हो रहा है, इससे बचने के लिए मैं महीनों तक मंत्रिमंडल की बैठकों में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी वार्ता में यह कहती रही कि तीनों विधेयक लाने के पहले एक बार किसानों की बात सुन लीजिए क्योंकि वे देश के अन्नदाता हैं। अन्यथा आंदोलन होगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहरे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। (शेष पेज 2 पर)

पेट्रोल-डीजल की कीमतें 73 साल में सबसे ज्यादा, यूपीए सरकार के बराबर लगे टैक्सः सोनिया गांधी

नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से (शेष पेज 2 पर)

आज का पत्रकार समस्याओ से परेशान

6 जनवरी को पत्रकार दिवस था , पत्रकार दिवस पर पत्रकारों को खुशी होती है अफसोस के 6 सालों से पत्रकारिता बदल गई है। अच्छे पत्रकारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 6 सालों में नये पत्रकारों ने जो न्यूज लगा रहे हैं उससे जनता पर खराब असर हो रहा है, हम सिनियर पत्रकारों की सच्ची खबरों को जनता के सामने लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रेस का जो पावर है उसको दबाने की कोशिश कि जा रही है। अच्छे चैनलों पर भी परेशानी हो रही है। खास बात यह है जो चैनलों को नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है वही न्युज बताते है और वो नेता के हित में होती है। आज देश में जो हालात है उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। आज कल अच्छे पत्रकार सच्ची खबरों को सामने लाकर बताने में दिक्कत हो रही है और जनता की हकिकत नहीं बतायी जा रही है तो उस पर लोगों का ध्यान हट जाता है, लेकिन हमारे देश में कही लोग ऐसे भी है जो अच्छे पत्रकारों को पसंद करते है । आज भी जनता से गुजारीश है , अच्छे पत्रकारों का साथ दें। आप की कोई भी समस्या या खबर हो तो इस नंबर पर 7498535286 व्हॉटसअप कर सकते हैं व्हिडिओ ऑरिजन्ल होना चाहिए और आपका फोन नंबर भी जरुरी है।

संपादकीय

समाधान की उम्मीद

किसानों का बढ़ता आंदोलन जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक भी। दिल्ली की सीमाओं पर अनेक जगह जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, उससे प्रशासन के कान खड़े हो जाने चाहिए। सबसे दुखद यह कि घोषित रूप से ऐसी रैली का अभ्यास 26 जनवरी के आयोजन को प्रभावित करने के लक्ष्य के साथ किया गया है। दिल्ली चलो के नाम पर 26 नवंबर को शुरू हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन तनाव बढ़ाने की दिशा में बढ़ चला है। किसानों को नए कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार किसानों के साथ अनेक बार वार्ता कर चुकी है, लेकिन समाधान की उम्मीद को बल नहीं मिला है। आज 8 जनवरी को किसान-सरकार वार्ता फिर प्रस्तावित है, लेकिन अफसोस, 7 जनवरी की शाम तक इस वार्ता को लेकर कोई नई उम्मीद या प्रस्ताव सामने नहीं आया। स्वाभाविक है, किसी भी लोकतंत्र में जब सरकार किसी आंदोलन की बात नहीं सुनती है, तो उस आंदोलन में शामिल लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं और किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए यही करना चाहते हैं। 2,500 से भी ज्यादा ट्रैक्टर का दिल्ली की सीमा पर पहुंचना अपने आप में ऐतिहासिक है। ट्रैक्टर गांवों व खेतों में चलाया जाने वाला वाहन है, पर अगर ऐसे वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में दौड़ेंगे, तो क्या होगा, सोच लेना चाहिए। नई दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार, करीब 124 प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर दोपहिया समेत करीब छह लाख वाहन रोज आते हैं। रोज इतने वाहन दिल्ली आते हैं कि ज्यादातर प्रवेश द्वारों पर गिनती भी नहीं होती। कौन नहीं जानता कि दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक व शैक्षणिक केंद्र है। अगर ज्यादा दिनों तक यहां यातायात को रोका जाएगा, तो जाहिर है, व्यवसाय और रोजगार पर असर पड़ेगा, जिसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के बारे में न केवल किसानों, बल्कि सरकार को भी सोचना चाहिए। यह तो अच्छा है कि अभी भी दिल्ली के कुछ प्रवेश द्वार खुले हैं और दिल्ली किसी तरह से चल रही है, लेकिन किसान अगर एक जगह बैठने के बजाय जगह-जगह रैलियां निकालने लगेंगे, तो फिर मुश्किलों का कारवां भी चलेगा। आज की वार्ता में सरकार को समाधान के मकसद से ही बैठना चाहिए। लोगों को ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी आज की वार्ता से उम्मीदें हैं। ध्यान रहे, 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन पर आगे सुनवाई करेगा। उसकी चिंता पहले भी सबके सामने आ चुकी है। मामले को संवाद के जरिए सुलझाने में ही सार है। जहां सरकार को जल्द समाधान के लिए काम करना चाहिए, वहीं किसानों को भी कुछ नरमी जरूर दिखानी चाहिए। देश भर में कृषि की जमीनी हकीकत, उदारीकरण और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा अड़ने से आंदोलन में उग्रता बढ़ने का खतरा है, जिसे झेलने की स्थिति में देश नहीं है। पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा, यह आंदोलन अगर लंबा खिंचा, तो लोगों का कृषि से मोहभंग भी बढ़ेगा। अब दोनों पक्षों को समग्रता में विचार करते हुए वार्ता के लिए बैठना चाहिए।

तैयार रहें जल्द मिल सकती है वैक्सीन की पहली खेप : केंद्र सरकार

नई दिल्ली,केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्दी ही मिल सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि आपूर्तिकर्ता टीके की आपूर्ति 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों पर करेगा। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बाकी 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उनके संबंधित सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो से मिलेगा। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के सलाहकार डॉ प्रदीप हलदर ने पांच जनवरी के पत्र में कहा, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्द मिल सकती है। उन्होंने कहा, इस संबंध में, आपसे आग्रह किया जाता है कि टीके की आपूर्ति को प्राप्त करने के लिए पहले

से ही तैयारी रखें। पत्र में कहा गया है कि टीके का जिलों में वितरण पंजीकृत लाभार्थियों के मुताबिक होगा, जिसके लिए जल्दी अलग से एक पत्र भेजा जाएगा। गौरतलब है कि देश के औषधि नियंत्रक ने रविवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और देश में ही विकसित की गई भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह तीन जनवरी को टीके के आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन में टीका उपलब्ध कराने के लिए तैयार है लेकिन टीका किस तारिख को लाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी। इस बीच, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आठ जनवरी को टीकाकरण का पूर्वाभ्यास होगा ताकि प्रत्येक जिले में टीके की आपूर्ति के लिए प्रभावी योजना और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

बच्चे करेंगे गलती तो मां-बाप को मिलेगी सजा, नासिक पुलिस का फरमान

नासिक, पतंग उड़ाने वाले पतंगबाजों के लिए यह बेहद ही अहम खबर है। आपकी गलती की सजा आपके मां-बाप को मिल सकती है। नायलॉन के मांझे की वजह से लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नासिक पुलिस ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब अगर बच्चों के पास नायलॉन का मांजा पाया जाता है तो उनके मां-बाप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। पूरे राज्य में नायलॉन के मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके धड़ल्ले से नायलॉन का मांझा बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। नासिक शहर में कुछ दिनों पहले भारतीय जाधव नाम की एक महिला की नायलॉन के मांझे की वजह से मौत हो गई थी। भारती नासिक के सातपुर इलाके में रहती थी। दुर्घटना के दिन भी वो हमेशा की तरह टू व्हीलर के जरिए अपने घर जा रही थीं। लेकिन द्वारका पुल के पास मांझे की वजह से उनके गले में गंभीर चोट आई। आनन-फानन में उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग दोबारा उठने लगी है। पिंपरी में भी मांझे की वजह से महिला डॉक्टर की मौत पुणे के पिंपरी इलाके में भी दो साल पहले एक महिला डॉक्टर की पतंग के मांझे की वजह से गला कटने से मौत हो गई थी। कृपाली कदम नाम की महिला डॉक्टर की मौत हुई थी। इसके पहले सुवर्णा मजूमदार नाम की मीडियाकर्मी की भी इसी प्रकार मांझे की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। इस मांझे का शिकार ना सिर्फ इंसान होते हैं बल्कि पक्षियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस मौत के मांझे के सबसे ज्यादा शिकार आसमान में कलाबाजियां खाने वाले पक्षी होते हैं।

बाकी पेज १ का

ये तो बस झांकी है,...

आज यूपी गेट पर किसानों ने सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए हवन भी किया है।
- हरियाणा : 26 जनवरी को किसानों की परेड मार्च में भाग लेने के लिए जींद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।
- नोएडाः भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने केंद्र सरकार द्वारा किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हुए महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च किया।
-गुरुग्राम : कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के समर्थन में फर्रुखनगर क्षेत्र के किसानों ने हाथों में किसान यूनियन का ध्वज थामे ट्रैक्टर मार्च निकाला और करीब दो घंटे तक पातली गांव की सीमा क्षेत्र में केएमपी सुपर एक्सप्रेस-वे पर शांति पूर्वक मार्च किया। किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। धरने के बाद किसान ट्रैक्टरों पर बैठ कर पलवल धरना स्थल की और रवाना हो गए। ट्रैक्टर मार्च व धरना प्रर्दशन के दौरान किसान भारी पुलिस बल भी पहुंच गया था। हालांकि संख्या कम होने से कोई जाम जैसी समस्या नहीं बनी।
- हरियाणा से दिल्ली आने वाले हुए परेशान, किसान ट्रैक्टर रैली से बाधित रहा पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी, अंदरूनी सड़कों पर लगा जाम।
- गाजियाबाद : बील अकबरपुर से वापस यूपी गेट लौट रहे अधिकांश ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर सिरसा टोल की तरफ रवाना हुए।
- तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अन्य किसान संगठनों के साथ एकजुटता दिखाते हुए दिल्ली के बुराड़ी में ट्रैक्टर रैली निकाली।

पीएम मोदी को किसानों से करनी...

प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा कि केंद्र देश में किसानों का भरोसा गंवा चुका है। बादल ने कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के दरवाजे पर मर रहे हैं। देश में अन्नदाताओं की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र के बीच चल रही बैठकों के बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा कि सात दौर की वार्ता के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। बादल ने कहा, ह्यह्लअगर कई दौर की बैठकों के बावजूद मंत्री किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शनकारी किसानों के साथ सीधे वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहे हैं।बादल ने कहा, किसानों के खिलाफ इस अपराध में केंद्र और राज्य सरकारें सीधे तौर पर भागीदार हैं। किसान जब धरना पर बैठे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री अपने फार्महाउस में मौज कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों के अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार में हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थीं और विधेयकों को पारित कराने के लिए लोकसभा में लाए जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।हरसिमरत के पति और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने तीनों कृषि विधेयकों पर चर्चा में भागीदारी करते हुए निचले सदन में उनके इस्तीफे की घोषणा की थी। कुछ दिन बाद भाजपा के साथ दशकों पुराना रिश्ता तोड़ते हुए शिरोमणि अकाली दल सत्तारूढ़ राजग से बाहर हो गया।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें 73 साल...

एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए। सोनिया ने एक बयान में कहा, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक ओर देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज मांगों के समर्थन में डटा हुआ है, वहीं देश की निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर भाजपा सरकार गरीब किसान व मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी है।उन्होंने यह भी कहा, कोरोना की चौतरफा मार से ध्वस्त अर्थव्यवस्था के बीच मोदी सरकार अपना खजाना भरने के लिए आपदा को अवसर बनाने में लगी है। आज कच्चे तेल की कीमत 50.96 डॉलर प्रति बैरल है यानी मात्र 23.43 रुपये प्रति लीटर। इसके बावजूद डीजल 74.38 रुपये और पेट्रोल 84.20 रुपये प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। ये पिछले 73 साल में सबसे अधिक है।कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया, अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने के बावजूद सरकार ने आम उपभोक्ता को इसका लाभ देने की बजाय उत्पाद शुल्क में बेतहाशा बढ़ोतरी करके मुनाफा वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साढ़े छह सालों में मोदी सरकार ने उत्पाद शुल्क बढ़ा कर लगभग 19 लाख करोड़ आम जनता की जेब से वसूले हैं।सोनिया के मुताबिक, गैस सिलेंडर के दामों को भी भाजपा सरकार ने बेतहाशा बढ़ा हर घर का बजट बिगाड़ा है।

मुम्बई की मेयर को दी थी जान से मारने की धमकी, गुजरात से गिरफ्तार हुआ आरोपी

मुम्बई, मुम्बई की महापौर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को गुजरात के जामनगर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की टीम को फोन करने वाले की लोकेशन जामनगर मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी को लेकर गुरुवार को मुंबई पहुंच सकती है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महापौर को पिछले साल 21 दिसम्बर को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन कर हिंदी में अभद्र शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि पेडनेकर ने हाल ही में दक्षिण मुम्बई के आजाद मैदान पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 506-क्क के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। पेडनेकर 2019 नवम्बर में महापौर चुई गई थीं।

मुंबई में आलू, प्याज के बोरों में हो रही ड्रग्स की सप्लाई, 106 किलो गांजा जब्त

मुंबई,

ड्रग्स माफियाओं ने मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई के लिए अलग-अलग मोडस ऑपरेंडी अपनाई है। अब पता चला है कि ये लोग आलू, प्याज के बोरों के जरिए भी शहर में ड्रग्स लाते हैं। डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया कि उनकी टीम ने तीन आरोपियों इशरत सिद्दीकी, अफरोज सिद्दीकी और आनंद तरडे के पास से 106 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये है। पुलिस ने वह टेम्पो भी अपने कब्जे में लिया है, जिसमें यह गांजा मिला था। टेम्पो धुले से आया था। उसमें आलू व प्याज के कई दर्जन बोरे रखे हुए गए थे। उन बोरों के बीच इस ड्रग को इस तरह छिपाया गया था कि किसी को शक न हो, लेकिन बांद्रा ऐंटीनार्कोटिक्स सेल के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल वाढवणे को किसी ने इस टेम्पो के विक्रोली में होने की टिप दे दी। इसी के बाद जब आलू, प्याज के बोरे उतरवाए गए, तो यह ड्रग्स मिली। जांच में पता चला कि ड्रग माफियाओं द्वारा ओडिशा और असम से ड्रग्स की सप्लाई धुले तक होती है। वहां से फिर इसकी मुंबई में तस्करी होती है। जांच अधिकारी इस ऐंगल से भी केस की जांच कर रहे हैं कि कहीं नक्सली तो इस ड्रग्स तस्करी के पीछे शामिल नहीं हैं।

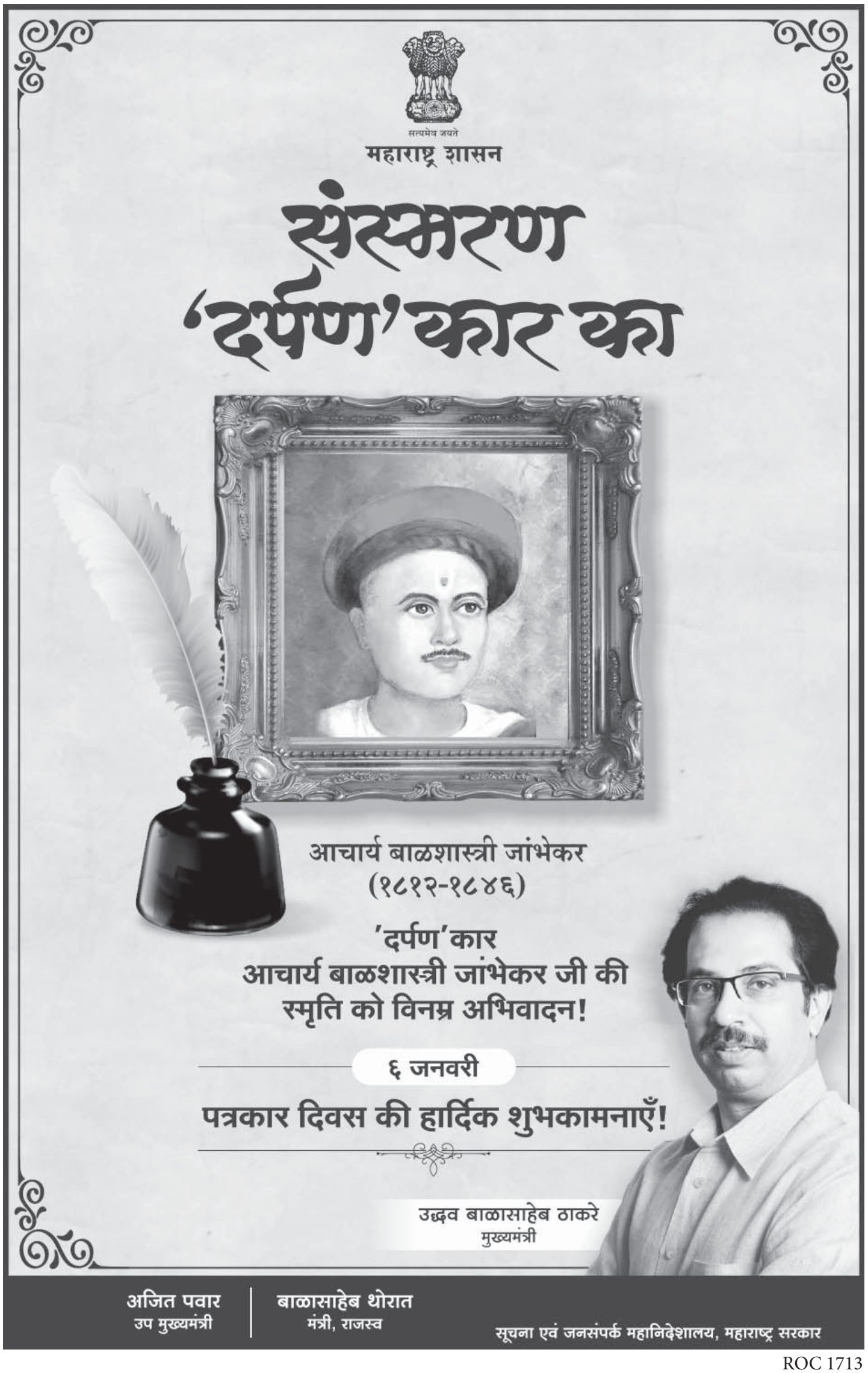

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

क्या कोविड-19 से सुरक्षित हैं किसान? तबलीगी जमात जैसे न हो जाएं हालात

नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को केन्द्र से पूछा कि क्या ये किसान कोराना संक्रमण से सुरक्षित हैं। तबलीगी जमात का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना पर अंकुश पाने के लिए बने दिशा-निदेर्शों का पालन होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे और निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। केंद्र सरकार दो सप्ताह में दाखिल करेगी रिपोर्ट चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस, बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई के दौरान केन्द्र से कहा कि आपको हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन से भी वैसी ही समस्या पैदा होने जा रही है। हमें नही मालूम कि क्या किसान कोविड से सुरक्षित हैं? वही समस्या फिर पैदा होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीत गया है। कोर्ट ने केन्द्र की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं?
इस पर मेहता ने जवाब दिया कि निश्चित ही ऐसा नहीं है। मेहता ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएंगे कि क्या किया गया है और क्या करने की जरूरत है?यह याचिका वकील सुप्रिय पंडिता ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से नहीं रोक सकी और निजामुद्दीन मरकज का मुखिया मौलाना साद अभी तक गिरफ्तारी से बच रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ओम प्रकाश परिहार ने कहा कि मौलाना साद के बारे में केन्द्र ने कोई बयान नहीं दिया है। इस पर बेंच ने परिहार से सवाल किया कि आपकी दिलचस्पी एक व्यक्ति में क्यों हैं? हम कोविड के मुद्दे पर हैं। आप विवाद क्यों चाहते हैं? हमारी दिलचस्पी है कि कोविड दिशानिदेर्शों का पालन होना चाहिए। बेंच ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोविड संक्रमण फैले नहीं और इससे संबंधित दिशानिदेर्शों का पालन हो। बेंच ने कहा कि नोटिस जारी किया गया है। इस पर प्रतिवादी अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करेंगे।केन्द्र सरकार ने पिछले साल पांच जून को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे पर बड़ी

संख्या में लोगों के एकत्र होने और तबलीगी जमानत के कार्यक्रम के आयोजन की घटनाओं की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने के प्रयासों के बारे में कोर्ट को विस्तार से अवगत कराया था। गृह मंत्रालय ने कहा था कि दिल्ली के इलाकों में फर्जी खबरों और गलत जानकारी की वजह से हजारों कामगार पिछले साल 28 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर सीमा पर एकत्र हो गए थे।

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं : कोर्ट

चेन्नई,
धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार से राज्य में एक मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना तलाशने को कहा।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी ने बुधवार को कहा, धार्मिक संस्कारों को सार्वजनिक हित और जीवन के अधिकार के अधीन होना चाहिए। धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। यदि महामारी की स्थिति में सरकार को कुछ उपाय करने हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
चीफ जस्टिस बनर्जी और जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति ने सरकार को निर्देश दिया कि तिरुचनापल्ली जिले में स्थित श्रीरंगम रंगानाथस्वामी मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों और अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना की तलाश करें। याचिकाकर्ता, रंगराजन नरसिम्हन ने हिंदू

धार्मिक और धर्मार्थ विभाग को निर्देश देने की मांग की कि प्राचीन श्रीरंगम मंदिर में उत्सवों और अनुष्ठानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए।
चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ कम रखने के लिए दुर्गा पूजा त्योहार के नियमन का आदेश दिया था। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सतीश परासरन ने कहा कि महामारी के दौरान कुछ त्योहार मनाए गए लेकिन अलग-अलग तारीख पर। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि धार्मिक प्रमुखों से परामर्श करके यह जांचें की लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना उत्सव आयोजित करने की संभावना क्या है। अदालत ने राज्य को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

11 महीनों में 2270 खुदकुशी, आखिर महाराष्ट्र में मौत को क्यों गले लगा रहे किसान?

मुंबई
महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को सत्ता पर काबिज हुए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। यह आंकड़ा साल 2020 के जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का है। हालांकि यह संख्या साल 2019 के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। साल 2019 में 2566 किसानों ने आत्महत्या की थी। मुआवजे के हकदार थे किसान
आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाडगे की निकाली गई जानकारी पर गौर करें तो यह पता चलता है जिन 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे।
यह जानकारी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय की तरफ से आरटीआई के तहत दी गई है। सरकार कर्ज में डूबे किसानों को मुआवजा देती है। अक्सर यह मुआवजा उनके परिजनों को मिलता है जो तकरीबन एक लाख रुपये तक होता है। जानकारी के अनुसार आधे से ज्यादा किसान विदर्भ इलाके के हैं। जिसे महाराष्ट्र की कॉटन बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस इलाके से तकरीबन 1230 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के सूखे इलाके वाली जगहों पर 693 किसानों ने आत्महत्या की है। जबकि उत्तर महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 322 किसानों का है।
पश्चिम महाराष्ट्र जिसे शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है वहां आत्महत्या के 25 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि कोंकण इलाके में एक भी सुसाइड सामने नहीं आया है। किसान नेता अजित नवले ने बताया कि सरकार ने किसानों की फसल को बीते सालों के मुकाबले इस वर्ष अधिक मात्रा में खरीदा है। बावजूद इसके किसानों को अपनी फसल स्थानीय व्यापारियों को बेचनी पड़ी। जिसकी वजह से किसानों को केंद्र सरकार की कृषि सम्मान योजना और राज्य की कर्ज माफी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया।

बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरी, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका

पूर्णिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के गंगा प्रसाद उत्क्रमित उच्च विद्यालय दमगड़ा पहुंचे। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जीविका के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आने वाले समय में इन तालाबों की देखभाल की जिम्मेदारी जीविका दीदी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं में जागृति आई है पढ़ाई से लेकर कमाई के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।

हर पल टाईम्स व हरपल टीवी न्यूज

आपकी न्युज इस व्हॉटसअप नंबर पर 7498535286 भेजें
कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है..

मालक, मुद्रक, प्रकाशक वसीम जे. खान ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॅम्प, चेंबूर, मुंबई -४० ००८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५ डी/ १. शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई - ४ ० ० ०४३ से प्रकाशित किया। संपादकः वसीम जे. खान. RNI NO:- MAHHIN/2011/24374
Email--harpaltimes.press@gmail.com 074985 35286 (सभी विवाद निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र मुंबई, महाराष्ट्र होगा।)